भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5061

02 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन के उद्देश्य

†5061. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस मिशन के अंतर्गत अनुमानित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) मूलभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और आंकड़ों के विकास के लिए इसके उद्देश्य क्या हैं और यह किस प्रकार भारत की स्थानिक आंकड़ा प्रणालियों के आधुनिकीकरण में योगदान देगा;

(घ) यह मिशन निर्णयन और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बेहतर आंकड़े उपलब्ध कराते हुए विशेषकर ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में क्षेत्रीय योजना और विकास में किस प्रकार सहायक होगा; और

(ङ) सरकार इस मिशन के अंतर्गत विकसित भू-स्थानिक आंकड़ों और अवसंरचना की दीर्घकालिक स्थिरता और सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करेगी और निरंतर अद्यतन और अनुरक्षण हेतु क्या उपाय किए जाएंगे?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की घोषणा की है जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण, शहरी योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के अभिकल्प को सुसाध्य बनाने के लिए देश भर में आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और आंकड़ों का विकास करना है।

(ग) से (ङ): मूलभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और आंकड़े अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने और कृषि (ग्रामीण क्षेत्रों) से लेकर उद्योगों, शहरी या ग्रामीण अवसंरचना के विकास, भूमि कार्यान्वयन, बैंकिंग और वित्त की आर्थिक गतिविधियों, संसाधनों, खनन, जल, आपदा प्रबंधन, सामाजिक योजना, वितरण सेवाओं आदि तक अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों सेवाओं में सुधार करने में सहायित करते हैं। मूलभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और आंकड़ों का विकास जिसमें नेशनल हॉरिज़ान्टल रिफेरेंस फ्रेम (एनएचआरएफ) और नेशनल वर्टिकल रिफेरेंस फ्रेम (एनवीआरएफ) से युक्त नेशनल जियोडेटिक भू-गणितीय रिफेरेंस फ्रेम शामिल है और इसमें ऑर्थोरेक्टीफाइड इमेजरी (ओआरआई) और जिओ-आईसीटी के साथ-साथ डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) शामिल हैं। अवसंरचना भारत की स्थानिक आंकड़ों प्रणालियों के आधुनिकीकरण में योगदान देगी। राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 के अनुसार, सर्वे ऑफ इंडिया उच्च रिज़ॉल्यूशन/उच्च स्थानिक सटीकता ऑर्थोइमेजरी बनाने और बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाएगा तथा निजी क्षेत्र डोमेन आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त ऐसे आंकड़ों के सृजन, रखरखाव और उपयोग के लिए स्वतंत्र होगा।

*****